निर्वाचन आयोग , भारत

बनाम

साका वेंकटा सुब्बा राव

भारत संघ - मध्यस्थ।

[पतंजलि शास्त्री, सी.जे., मुखर्जी, विवियन बोस,

गुलाम हसन और भगवती, न्यायाधिपतिगण]

अनुच्छेद 132, 192, 226 भारत का संविधान, 1950-उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति- परिसीमा-क्षेत्राधिकार से बाहर रहने वाले व्यक्ति के लिए रिट जारी करने की शक्ति- मद्रास विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग नई दिल्ली को निर्देश -मद्रास उच्च न्यायालय को चुनाव आयोग के विरूद्ध रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार-चुनाव पूर्व की निरर्हत प्रभाव -एकल न्यायाधीश से अपील।

प्रत्यर्थी जिसे दोषी ठहराया गया था और सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, मद्रास विधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर मद्रास के राज्यपाल के द्वारा चुनाव आयोग जिसका स्थायी रूप से कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को निर्दिष्ट किया गया। प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी निरर्हत था और उसे विधानसभा में बैठने और मतदान करने की अनुमति दी जा सकती थी? प्रत्यर्थी द्वारा इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की गई, जिसमे ये निवेदन किया गया की चुनाव आयोग द्वारा उसकी विधानसभा की सदस्यता के लिए उसकी कथित निरर्हता से संबधित जांच को रोका जावे।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दो सीमाओं के अधीन है- ऐसी रिट क्षेत्राधिकार के

अधीन क्षेत्रीय विषय से बाहर नहीं हो सकती और वह व्यक्ति या प्राधिकारण जिसको उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी रिट जारी करने का अधिकार है वह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर हो या वह निवास या स्थान के आधार पर क्षेत्रिय सीमा में हों। इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय को चुनाव आयोग के विरूद्व संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 190(3) और 192(1) केवल वही लागू हैं जहा उन निरर्हताओ के लिए जिनके अधीन जहा सदस्य चुनाव में निर्वाचित होने के बाद निरर्हताओ का विषय बन जाता है और उसके बाद उसे इस तरह चुना जाता है और प्रत्यर्थी की निरर्हता जो चुनाव से बहुत पहले उत्पन हुई थी की जांच करना न तो राज्यपाल और न ही चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में था।

एक अधिकरण या प्राधिकरण जो स्थायी रूप से और सामान्य रूप से उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहा है, को किसी उच्च न्यायालय की उसे क्षेत्रिय सीमा के भीतर कार्यशील नहीं माना जा सकता और सिर्फ इसलिए की उस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, केवल उन क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर जिसमे पक्षकरों के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए प्रयोग करता है।

तथ्य यह है कि मामला संबंधित निर्णय के लिए इसे निर्देशित किया गया था कि मद्रास में विधान सभा में विपक्ष पक्ष के सदन में बैठने और वोट देने का अधिकार और विवाद के पक्षकारों जो की मद्रास राज्य में निवास करते हो मद्रास उच्च न्यायालय को चुनाव आयोग के खिलाफ रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है।

संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या एकल न्यायाधीश अंतिम आदेश कीअपील की जा सकती हैं बशर्ते अपेक्षित प्रमाण पत्र दिया गया हो।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 205/1952।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की विशेष मूल क्षेत्राधिकार के अधीन मद्रास उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र (सुब्बा राव जे) मे संस्थित रीट याचिका संख्या 599/1952 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 16 सितंबर 1952 से अपील।

एम.सी. सीतलवाड, भारत के महान्यायवादी (जी.एन. जोशी, उनके साथ)- अपीलकर्ता और मध्यस्थ के लिए।

मोहन कुमारमंगलम- प्रत्यर्थी के लिए।

27 फरवरी 1953- न्यान्यलय का निर्णय दिया गया – द्वारा - पतंजलि शास्त्री (सी.जे) - यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र के एकल न्यायाधीश के उस आदेश के विरूद्‌ध है, जिसमें चुनाव आयोग, जो कि राष्ट्रपति द्वारा गठित एक वैधानिक प्राधिकरण और जिसका स्थायी कार्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं, के द्वारा मद्रास विधानसभा की सदस्यता के लिए प्रत्यर्थी की कथित निरर्हता की जांच करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रीट जारी की गई थी।

प्रत्यर्थी को पूर्वी गोदावरी के सत्र न्यायाधीश द्वारा 1942 में दोषी ठहराया गया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, और उसे 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के अवसर पर रिहा कर दिया गया। जून, 1952 में, मद्रास विधानसभा के काकीनाडा निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित सीट के लिए उप-चुनाव होना था और प्रत्यर्थी, स्वय को एक उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहता था, लेकिन स्वय को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 7 (ख) के तहत निरर्हत होने से क्योंकि उसकी रिहाई को पांच साल भी नहीं बीते थे, उसने 2 अप्रैल, 1952 को आयोग में छूट के लिए आवेदन किया ताकि वह चुनाव लड़ने में सक्षम हो सकें। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मई 1952 तक आवेदन का कोई जवाब नहीं मिला,

प्रत्यर्थी ने उस दिन अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन पत्र की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर या किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा इस नामांकन पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी। चुनाव 14 जून, 1952 को हुआ था और सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले प्रत्यर्थी को 16 जून, 1952 को निर्वाचित घोषित किया गया था। चुनाव का परिणाम 19 जून 1952 को फोर्ट सेंट जॉर्ज गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था और प्रत्यर्थी ने 27 जून, 1952 को विधानसभा के सदस्य के रूप में अपनी सीट ग्रहण की। इस बीच, आयोग ने छूट के लिए प्रत्यर्थी के आवेदन को खारिज कर दिया और 13 मई, 1952 को अपने पत्र द्वारा प्रत्यर्थी को इस तरह की अस्वीकृति की सूचना दी, जो हालांकि उसे प्राप्त नहीं हुई। 3 जुलाई, 1952 को, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में आयोग से प्राप्त एक पत्र पढ़ा, "ऐसी कार्रवाई के लिए जो जिसे वह लेना उचित समझे में ", उनके संज्ञान में लाया गया। यह तथ्य की छूट के लिए प्रत्यर्थी का आवेदन खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी की निरर्हता के बारे में एक प्रश्न उठाया गया। अध्यक्ष ने प्रश्न को मद्रास के राज्यपाल के पास निर्दिष्ट कर दिया, जिन्होंने मामले को संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार "राय" के लिए आयोग को भेज दिया। इसके बाद प्रत्यर्थी ने निर्देश करने की सक्षमता और राज्यपाल द्वारा उस पर की गई कार्यवाही को चुनौती दी। आयोग ने प्रत्यर्थी को सूचित किया कि उसका मामला 21 अगस्त, 1952 को सुना जाएगा। तदनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (जो कुछ समय के लिए आयोग के एकमात्र सदस्य थे,) मद्रास गए और 21 अगस्त, 1952 को प्रत्यर्थी के वकील और मद्रास राज्य के महाधिवक्ता को सुना। जब इस बात पर सहमति हुई कि यदि याचिकाकर्ता के वकील कोई और अभ्यावेदन या तर्क देना चाहते हैं तो इसे लिखित रूप में 28 अगस्त, 1952 तक दिल्ली में आयोग को भेजा जाना चाहिए और आयोग को राज्यपाल को अपनी राय देने से पहले उन पर विचार मे लिया जाना चाहिए।

उसी दिन (21 अगस्त, 1952) प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन किया और तर्क दिया कि अनुच्छेद 192 केवल वहां लागू होता है जहां एक सदस्य निर्वाचित होने के बाद निररहता के अधीन हो जाता है, लेकिन वहां नहीं, जहां निररहता चुनाव से बहुत पहले उत्पन्न हुई थी, जैसा की यहाँ है। उस स्थिति में एकमात्र उपाय चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव की वैधता को चुनौती देना था। तदनुसार, उन्होंने परमादेश या प्रतिषेध की रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की, जिसमें आयोग को मद्रास के राज्यपाल द्वारा किए गए निर्देश के साथ आगे बढ़ने से रोकने का आदेश दिया जाए, जिन्हें हालांकि, कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं बनाया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका की प्राप्ति पर, आयोग ने इस आधार पर रिट जारी करने की न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति की कि आयोग "उस क्षेत्र सीमा में नहीं था जिसके संबंध में उच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया था। "आवेदन की स्थिरता पर एक और आपत्ति इस आशय से भी उठाई गई कि आयोग की राय मांगने में राज्यपाल की कार्रवाई को अनुच्छेद 361 (1) के तहत प्रदान की गई छूट के मद्देनजर चुनौती नहीं दी जा सकती है, और आयोग स्वयं जिसे निररहता के प्रश्न पर "निर्णय" नहीं करना था, बल्कि केवल अपनी "राय" देनी थी, वह कार्यवाही अनुच्छेद 226 के तहत नहीं की जा सकती। आयोग ने गुणावगुण के आधार पर तर्क दिया कि अनुच्छेद 192, अपने सही अर्थो मे, चुनाव से पहले और बाद में उत्पन्न होने वाली निररहत दोनों के मामलों में लागू होता है और प्रत्यर्थी की निररहत के प्रश्न पर मद्रास राज्य के राज्यपाल के निर्देश और बाद में आयोग की राय के लिए उसे संदर्भित करना दोनों ही निर्देश सक्षम और वैध थे।

प्रार्थना पत्र पर न्यायाधिपति सुब्बा राव ने सुनवाई की, जिन्होंने प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया और माना कि अनुच्छेद 192 अपने सही अर्थो मे केवल पश्चातवर्ती निरहर्ता के मामलों पर लागू होता है और इसलिए आयोग के पास चुनाव से बहुत पहले उत्पन्न हुई। प्रत्यर्थी की निररहता से संबंधित कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

तदनुसार, उन्होंने एक रिट जारी की जिसमें आयोग को अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल द्वारा संदर्भित प्रश्न के संबंध में जांच को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया। यद्धपि, विद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेद 132 के तहत एक प्रमाण पत्र दिया कि मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल है और आयोग द्वारा तदनुसार यह अपील की गयी है।

श्री मोहन कुमारमंगलम द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी, जिन्होंने अपनी उल्खनीय योग्यता के साथ प्रत्यर्थी के लिए मामले में तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के निर्णय पर लाई गई अपील संविधान के अनुच्छेद 133 (3) के तहत वर्जित है, भले ही इसका प्रमाण पत्र दिया गया हो। जिसमे विद्वान न्यायाधीश ने उन आपत्ति को खारिज कर दिया जो उनके समक्ष भी उठाई गई थी। यह तर्क दिया गया कि, जहां तक सिविल मामलों का सवाल है, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्तता का प्रमाण पत्र देने के लिए अनुच्छेद 133(1)(ग) में अधिक व्यापक प्रावधान अनुच्छेद 132(1) को पूरी तरह से अतिछादित करते हैं जो केवल एक विशिष्ट आधार से संबन्धित है, अर्थात्, संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और इसलिए ऊपर उल्लिखित आधार सहित किसी भी आधार पर उपयुक्तता का प्रमाण पत्र देने की न्यायालय की शक्ति को अनुच्छेद 133(1)(ग) के परिणामस्वरूप ऐसी शक्ति का प्रयोग उस अनुच्छेद के खंड (3) के शुरुआती शब्दों से बाहर हो जाता है जो उच्च न्यायालय को एकल न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ अपील को रोकता है। इस तर्क को अनुच्छेद के खंड (2) और अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के संदर्भ में सुदृढ़ करने की मांग की गई थी, जिसमें संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कानून के महत्पूर्ण प्रश्नों से जुड़ी अपीलों जिनको अनुच्छेद 132 के तहत प्राप्त प्रमाण पत्र के बिना भी लाया जा सकता है। तर्क में कोई बल नहीं है। जबकि यह सच है कि अनुच्छेद 132 के तहत प्रमाण पत्र के बिना दायर अपीलों में संवैधानिक प्रश्न उठाए जा सकते हैं। उस अनुच्छेद की शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि "उच्च न्यायालय के किसी भी

निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश" से अपील की अनुमति है, बशर्ते, अपेक्षित प्रमाण पत्र दिया गया हो, और अपील के अधिकार पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जिसमे न्यायाधीशों की संख्या का संदर्भ जिनके द्वारा ऐसा निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश पारित किया गया था। यदि एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय आदि के मामले में अपील के अधिकार को बाहर करने का इरादा होता, तो अनुच्छेद 133(3) के शुरुआती शब्दों में भी अनुच्छेद 132 का संदर्भ शामिल करना आसान होता, जैसा कि अनुच्छेद 133(3) के ठीक पूर्ववर्ती खंड में। यदि प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार कर लिया गया, तो न केवल अनुच्छेद 132 निरर्थक हो जाएगा, बल्कि उस अनुच्छेद के स्पष्टीकरण का उद्देश्य भी, जिसे एस. कुप्पुस्वामी राव बनाम राजा [(1)] [1947] एफ.सी.आर. 180) में संघीय न्यायालय के फैसले को रद्द करने के लिए निर्धारित किया गया था और इस प्रकार किसी मामले की जड़ तक जाने वाले संवैधानिक मुद्दों के त्वरित निर्धारण को सुरक्षित करना भी परास्त हो जाएगा, ज्योंकि स्पष्टीकरण को अनुच्छेद 133 (1) में प्रयुक्त समान अभिव्यक्ति "अंतिम आदेश" पर लागू नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की पूरी व्यवस्था स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्नों को कार्यवाही की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना, जिसमें वे उठ सकते हैं, एक विशेष श्रेणी में रखा गया है और ऐसे प्रश्नों से जुड़े मामलों में व्यापक आयाम की अपील का अधिकार है। तदनुसार हम प्रारंभिक आपत्ति को रद्द करते हैं और मानते हैं कि अपील पोषणीय है।

अब अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों के प्रश्न की ओर ध्यान देते हुए यह देखा जाएगा कि अनुच्छेद 225 मौजूदा उच्च न्यायालयों को वही क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ जारी रखता है जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले उनके पास थीं। यद्यपि इस बिंदु पर न्यायिक राय में कुछ विरोधाभास था, लेकिन पार्लाकिमेडी मामले [(1)] 70 आइ.ए. 129) में प्रिवी काउंसिल द्वारा आधिकारिक तौर पर यह निर्णय लिया गया था कि मद्रास उच्च न्यायालय बॉम्बे और कलकत्ता के उच्च न्यायालय एक

ही स्थिति में थे - उनके पास अपने मूल नागरिक क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं से परे उच्च विशेषाधिकार रिट जारी करने की कोई शक्ति नहीं थी, और उन सीमाओं के भीतर ऐसी रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई थी जो मद्रास के प्रेसीडेंसी टाउन पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रही थी और 1861 के चार्टर अधिनियम के अनुसरण में स्थापित उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारत में अन्य उच्च न्यायालयों के पास ऐसी रिट जारी करने की कोई शक्ति नहीं थी।

उस स्थिति में, संविधान के निर्माताओं ने नई व्यवस्था में लोगों के लिए कुछ बुनियादी सुरक्षा उपाय प्रदान करने का निर्णय लिया, जिन्हें वे मौलिक अधिकार कहते थे, जाहिर तौर पर उन्होंने इस अधिकार को लागू करने के लिए एक त्वरित और सस्ता उपाय प्रदान करना आवश्यक समझा और यह पाते हुए कि इंग्लैंड में न्यायालयों ने विशेषाधिकार रिट विकसित की थी और जब भी तत्काल और निर्णायक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी, तब उपयोग किया जाता था। विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त थे, उन्होंने राज्यों के क्षेत्र में, उच्च न्यायालयों को नई और व्यापक शक्तियां प्रदान कीं जिनमे मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करना, ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति, आदि, "किसी अन्य उद्देश्य के लिए" को भी स्पष्ट रूप से इस देश के सभी उच्च न्यायालयों को कुछ हद तक इंग्लैंड में किंग्स बेंच न्यायालय के समान स्थिति में रखने के उद्देश्य से शामिल किया जा रहा है. लेकिन जिस प्रकार जितनी शक्तियां प्रदान की गईं, उनके प्रयोग पर दोहरी सीमा लगा दी गई। सबसे पहले, शक्ति का प्रयोग "उन क्षेत्रों में किया जाना है। जिनके संबंध में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है", यानी, अदालत द्वारा जारी किए गए रिट इसके अधीन क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में नहीं चल सकते हैं । दूसरे, जिस व्यक्ति या प्राधिकारण को उच्च न्यायालय को इस तरह के रिट जारी करने का अधिकार है, वह

"उन क्षेत्रों के भीतर" होना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट अर्थ है कि उन्हें उन क्षेत्रों के भीतर निवास या स्थान द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

ऐसी सीमाएं वास्तव में इंग्लैंड में एक विशेष उपाय के रूप में विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति की उत्पत्ति और विकास का एक तार्किक परिणाम है। ऐसी शक्ति किंग्स बेंच के न्यायालय के मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार का कोई हिस्सा नहीं बनती थी। जैसा कि प्रो. होल्ड्सवर्थ ने बताया है (अंग्रेजी कानून का इतिहास, खंड 1, पृ. 212 आदि) इन रिटों की उत्पत्ति उनके अधिकारियों द्वारा कानून के उचित पालन पर राजा की अधीक्षण की विशेषाधिकार शक्ति के प्रयोग में हुई थी और न्यायाधिकरण, और राजा की पीठ के न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए गए थे, ताकि राजा को पता चल सके कि उसकी प्रजा को कानूनी रूप से कैद किया गया था या नहीं। उत्प्रेषण, ताकि वह जान सके कि उनके खिलाफ शुरू की गई कोई कार्यवाही कानून के अनुरूप है या नहीं। परमादेश, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके अधिकारी ऐसे कार्य करें जो वे कानून और निषेध के तहत करने के लिए बाध्य थे, अपने क्षेत्र में अवर न्यायाधिकरणों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य करें। पार्लाकिमेडी मामले [(1)](70 आइ.ए.129,140) में फैसले में प्रारंभिक टिप्पणियाँ भी देखें। इस प्रकार ये रिट विशेष रूप से उन व्यक्तियों या अधिकारियों को निर्देशित की जाती थीं जिनके खिलाफ निवारण की मांग की गई थी और उन्हें जारी करने वाली न्यायालय में वापस करने योग्य बनाया गया था और अवज्ञा के मामले में, अवमानना के लिए कुर्की द्वारा लागू किया जा सकता था। उपचार के विशेष रूप की इन विशेषताओं ने इसके प्रभावी उपयोग के लिए यह आवश्यक बना दिया कि जिन व्यक्तियों या अधिकारियों को न्यायालय को ये रिट जारी करने के लिए कहा गया था, वे उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर हों। हम नीचे दिए गए विद्वान न्यायाधीश से सहमत होने में असमर्थ हैं कि यदि कोई न्यायाधिकरण या प्राधिकरण स्थायी रूप से स्थित है और सामान्य रूप से अपनी गतिविधियों को कहीं और चला रहा है तो उन

क्षेत्रीय सीमा के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। ताकि वहां के पक्षों के अधिकारों को प्रभावित किया जा सके, ऐसे न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर "कार्यकर्ता" के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत उसके अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

हालांकि, प्रत्यर्थी के वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय के पास नई दिल्ली में आयोग को एक रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार था क्योंकि प्रश्न मद्रास विधान सभा में प्रत्यर्थी के बैठने और मतदान करने के अधिकार से संबंधित निर्णय के लिए इसे संदर्भित करता था और विवाद के पक्षकार भी मद्रास राज्य में रहते थे. यह दावा किया गया था कि यह स्थिति, अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के बाहर के व्यक्तियों पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली अदालत के अनुरूप थी,बशर्ते कि कार्यवाही का कारण उन सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ हो। पार्लाकिमेडी मामले में [(1)] 70 आइ.ए. 129) प्रिवी काउंसिल की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था। "क्षेत्राधिकार के प्रश्न को सारगर्भित माना जाना चाहिए और शहर में राजस्व बोर्ड को उसके स्थान के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने जैसे मामले का दावा करना सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार की सीमा में नहीं होगा। इस तरह का दृष्टिकोण पक्षकारों के बीच गंजाम में रैयती होल्डिंग्स के किराए के निस्तारण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र देगा अन्यथा नहीं, यह उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है, जो उस राजस्व अधिकारी पर नहीं होता जिसने मामले में पहली बार निर्णय किया था।" हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। यह नियम कि कार्यवाही का कारण वाद में क्षेत्राधिकार को आकर्षित करता है, वह वैधानिक अधिनियमन पर आधारित है और अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाली रिट पर लागू नहीं हो सकता है, जो कार्रवाई के किसी भी कारण या जहां यह उत्पन्न होता है, का कोई संदर्भ नहीं देता है, लेकिन उन क्षेत्रों के भीतर व्यक्ति या प्राधिकारी की उपस्थिति पर जोर देता है जिसके संबंध में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है न ही ऊपर उद्धृत

टिप्पणियों से बहुत अधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। उक्त मामला निश्चित रूप से उचित लगान के व्यवस्थापन के लिए एक विशेष राजस्व अधिकारी के समक्ष मद्रास उच्च न्यायालय के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा से परे स्थित पार्लाकिमेडी की जमींदारी संपत्ति के भीतर हिस्सेदारी की कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था। असंतुष्ट रैयतों ने राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए समझौते कि राजस्व बोर्ड जिसका कार्यालय मद्रास में था, में अपील की.अपील को बोर्ड के एक सदस्य ने स्वीकार कर लिया और रैयतों की इच्छानुसार लगान कम कर दिया। जमींदार ने राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण के माध्यम से अपील की जिसने वृद्धि को मंजूरी दे दी। इसके बाद रैयतों ने राजस्व बोर्ड जिसने मद्रास शहर में शिकायत के अनुसार आदेश पारित किया की कार्यवाही को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कि गई. प्रिवी काउंसिल ने क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से विचार किया:-

> "(ए) स्वतंत्र रूप से स्थानीय नागरिक क्षेत्राधिकार से जिसका उपयोग उच्च न्यायालय प्रेसीडेंसी शहर पर करता है; या
>
> (बी) केवल उस कारण से की, शहर के भीतर राजस्व बोर्ड के स्थान को एक प्रसंग के रूप में।"

प्रश्न (ए) पर, उन्होंने 1800 के चार्टर के खंड 8 के तहत प्रेसीडेंसी टाउन से परे उत्प्रेषण जारी करने के लिए मद्रास सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की जांच की, जैसा कि यह सुझाव दिया गया था कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों में उत्तराधिकारी रहा, जिसे पूरे प्रांत में इंग्लैंड में किंग्स बेंच के न्यायालय के समान विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्तियाँ दी गई थीं, और उन्होंने दर्ज किया उनका निष्कर्ष इस प्रकार है:

"माननीय न्यायधिपतियों की राय इस बात पर नहीं है कि गंजम के भारतीय निवासियों के बीच उस जिले में भूमि के देय किराए के बारे में विवाद का फैसला करने वाली कंपनी की किसी देश की अदालत को सही करने या नियंत्रित करने का सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार होगा।"

फिर, प्रश्न (बी) से संबंधित और बेसेंट्स मामले [1] 46 आइ.ए. 176 में उनके फैसले का जिक्र करते हुए कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में उत्प्रेषण जारी करने की शक्ति थी, उन्होंने माना कि यह सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है कि "गंजम में भूमि के किराए में समझौता के लिए केवल राजस्व बोर्ड के स्थान के आधार पर एक निकाय के रूप में किया जाता है जो आम तौर मद्रास शहर का निवासी है या उसके भीतर स्थित है, या

इस आधार पर की जिस आदेश की शिकायत की गई है वह शहर के भीतर किया गया था। यदि ऐसा है, तो ऐसा प्रतीत होता है की शहर के बाहरी इलाके से परे राजस्व बोर्ड को हटाने से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बचा जा सकेगा और अपील लाए जाने की स्थिति के अलावा इसे कभी भी नहीं किया जाएगा या राजस्व बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण की कार्यवाही की गई।"

इसके बाद पहले से ही उद्धृत अंश का अनुसरण किया गया जिस पर प्रतिवादी के वकील ने विशेष बल दिया। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि निर्णय उस व्यक्ति या प्राधिकरण की, जिसे रिट जारी की जानी है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर उपस्थिति या स्थान की अवश्यकता को आधार मानने का कोई अधिकार नहीं है । इसे जारी करने की शक्ति है।

माननीय न्यायाधिपतियों ने माना, जिस अजीब स्थिति से वे निपट रहे थे, वह मद्रास शहर में अपीलीय प्राधिकारी का स्थान क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए पर्याप्त

आधार नहीं था, जबकि दोनों विषय-वस्तु, अर्थात्, गंजम में भूमि के लिए किराए का समझौता, और प्रथम दृष्टया समझौते के लिए अधिकृत राजस्व अधिकारी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा से बाहर थे। यदि मद्रास न्यायालय को मद्रास में अपीलीय प्राधिकारी को उत्प्रेषण रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार के रूप में मान्यता दी गई तो यह व्यावहारिक रूप से गंजम में राजस्व अधिकारी और वहां की भूमि के लिए किराए के निपटान पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मान्यता देगा, जो न्यायाधिपतियों ने माना कि यह कभी नहीं था। यह उस मामले का "सार" था जिसे वे देख रहे थे, और उनकी टिप्पणियाँ इस दृष्टिकोण का कोई समर्थन नहीं करती हैं कि यदि विषय-वस्तु या कार्यवाही का कारण और संबंधित पक्ष क्षेत्राधिकार की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर थे, तो उच्च न्यायालय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को विशेषाधिकार रिट जारी कर सकता है जो उन सीमाओं के भीतर नहीं हैं। किसी भी मामले में, संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे के उद्देश्य या शब्दों के समान वैधानिक प्रावधान के निर्माण अभिप्राय नहीं किया, और उस अनुच्छेद के अभिप्राय में बहुत अधिक सहायता नहीं की है।

यह कहा गया था कि यह अनुध्यात नहीं किया जा सकता था कि मद्रास राज्य का एक निवासी, दिल्ली में स्थित एक प्राधिकरण द्वारा उस राज्य में अपने अधिकारों के प्रयोग में हस्तक्षेप की धमकी से व्यथित महसूस कर रहा है और अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य कर रहा हो, उसे इसके पंजाब उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 तहत अपना उपचार खोजना चाहिए। यह कहना असुविधा के उनके तर्क का पर्याप्त उत्तर है की , अनुच्छेद की भाषा यथोचित रूप से स्पष्ट होने के कारण, यह अनुमान लगाना व्यर्थ है कि क्या विचार किया गया था या क्या नहीं किया गया था।

हमारा ध्यान उस स्थिति से संबंधित उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया है, जहां पहली बार किसी मामले पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का दावा करने वाला प्राधिकरण एक राज्य में स्थित है और अपीलीय प्राधिकरण दूसरे

राज्य में स्थित है। इस अपील के प्रयोजनों के लिए यह तय करना आवश्यक नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में किस उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार होगा।

वर्तमान मामले में अनुच्छेद 226 की प्रयोज्यता के बारे में हमने ऊपर जो विचार व्यक्त किया है उसमें इस प्रश्न पर चर्चा करना अनावश्यक है कि क्या अनुच्छेद 192(1) केवल उन सदस्यों पर लागू होता है, जो पहले से ही निर्वाचित होकर चुनाव के बाद होने वाली घटनाओं के कारण निरर्हतो का विषय बन गए हैं। लेकिन हमारे सामने पूरी तरह बहस को सुनने के बाद, हम उस पर अपनी राय व्यक्त करना सही समझते हैं, खासकर तब जब दोनों पक्षों ने इसके सामान्य महत्व को देखते हुए हमें ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया है।

संविधान के प्रासंगिक प्रावधान जिन पर इस प्रश्न का निर्णय निर्भर करता है वे इस प्रकार हैं:

190. (3) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य---

(ए) अनुच्छेद 191 के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है; या

(बी) अध्यक्ष या सभापति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपनी सीट से इस्तीफा दे देता है, जैसा भी मामला हो,

उसकी सीट खाली हो जाएगी,

191. (1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हत होगा।

(ए) यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत पहली अनुसूची में निर्दिष्ट लाभ का कोई पद धारण करता है, राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा उसके धारक को निरर्हत नहीं घोषित करने वाले पद के अलावा;

(बी) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(सी) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(डी) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है;

(ई) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निरर्हत घोषित किया गया है।

192. (1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में उल्लिखित किसी के निरर्हतो के अधीन हो गया है, तो उस प्रश्न को राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा.

(2) ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पहले, राज्यपाल चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उस राय के अनुसार कार्य करेंगे।

193. यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है..........जब की वह जानता है कि वह इसकी सदस्यता के लिए योग्य नहीं है या वह निरर्हत है या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों द्वारा उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है, तो वह प्रत्येक दिन के संबंध में जिस दिन वह बैठता है या

मतदान करता है, पांच सौ रुपये प्रति दिन के जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 1942 में प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि और सजा ने उसे अनुच्छेद, 191 (1) (ड) सपठित संसद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 7 के तहत विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने पर निरर्हत घोषित कर दिया, 15 अगस्त, 1947 को उनकी रिहाई के बाद से पांच साल की अवधि, चुनाव की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार प्रतिवादी 15 मार्च 1952 को अपने नामांकन से पहले से ही के निरर्हता के अधीन था। क्या यह कहा जा सकता है कि वह अनुच्छेद 192के अंतर्गत उस निरर्हतो के अधीन आ गया है.. ? पक्षकारो के विरोधाभाषी तर्क ऊपर उद्धृत प्रावधानों के संदर्भ में उस शब्द पर रखी जाने वाली सही व्याख्या पर केंद्रित थे।

महान्यायवादी ने तर्क दिया कि "सदस्यों की निरर्हता" से संबंधित प्रावधानों के पूरे प्रावरण अर्थात अनुच्छेद 190 से 193, को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, और चूंकि अनुच्छेद 191 और 193 स्पष्ट रूप से पहले से मौजूद और पशचात्वर्ती निरर्हता दोनों को कवर करते हैं। अनुच्छेद 190 और 192 को भी इसी तरह दोनों प्रकार की निरर्हता से संबंधित समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार ये सभी प्रावधान मिलकर एक अभिन्न व्यवस्था बनाते हैं जिसके तहत निरर्हता निर्धारित की जाती हैं और उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के निर्धारण के लिए तंत्र भी प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 190 (3) और 192 (1) में "बनना" शब्द का उपयोग, इस संदर्भ में, पूर्ववर्ती निरर्हता को भी इसके दायरे में शामिल करना अनुचित नहीं है, क्योंकि निरर्हता के अधीन बनना "विधानमंडल के सदन का सदस्य" से समर्पित है और एक व्यक्ति जो पहले से ही अयोग्य होने के कारण बिना किसी अनुचित तरीके से निर्वाचित हो जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि वह निर्वाचित होते ही सदस्य के रूप में निरर्हता के अंतर्गत हो जाता है। तर्क ध्वनि से अधिक सरल है. संविधान के अनुच्छेद 191 जो चुनाव के साथ-

साथ सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हताओ का एक ही सेट निर्धारित करता है, और अनुच्छेद 193 जो निरर्हत होने पर सदन मे बैठने और मतदान करने के लिए दंड निर्धारित करता है, स्वाभाविक रूप से पहले से मौजूद और पशचात्वर्ती निरर्हता दोनों को कवर करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों को कवर करने के लिए अनुच्छेद 190 (3) और 192 (1) को भी साथ लिया जाना चाहिए। उनका अर्थ इस्तेमाल की गई भाषा पर निर्भर होना चाहिए, जो हमें लगता है, उचित रूप से स्पष्ट है। हमारी राय में ये दोनों अनुच्छेद एक साथ चलते हैं और एक उपाय प्रदान करते हैं जब कोई सदस्य सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद निरर्हत हो जाता है। अनुच्छेद 190(3) में "विषय बन जाता है" और अनुच्छेद 192(1) में "विषय बन गया है" शब्द न केवल निर्वाचित होने के बाद सदस्य की स्थिति में बदलाव का संकेत देते हैं, बल्कि यह प्रावधान भी करते हैं कि उसकी सीट उसके रिक्त होने पर, अर्थात्, जो सदस्य पहले स्थान भर रहा था वह उसके निरर्हत हो जाने पर रिक्त हो जाता है, इस दृष्टिकोण को और पुष्ट करता है कि अनुच्छेद केवल मौजूदा सदस्य पर विचार करते हुए अपात्रता उत्पन्न करने पर विचार करता है। यह सुझाव कि अनुच्छेद 190(3) में प्रयुक्त भाषा को पहले से मौजूद निरर्हतो पर समान रूप से लागू किया जा सकता है क्योंकि एक सदस्य को निर्वाचित होते ही अपनी सीट खाली करनी पड़ सकती है, यह एक बनावटी और असुगम है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। महान्यायवादी ने स्वीकार किया कि यदि "है" शब्द को "बन जाता है" या "बन गया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यह उनके द्वारा दिए गए अर्थ को अधिक उचित रूप से व्यक्त करेगा, लेकिन वह यह कहने में असमर्थ थे कि इसका उपयोग क्यों नहीं किया गया था।

यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 190(3) और 192(1) एक सदस्य के रूप में चुनाव के बाद उत्पन निरर्हतो से संबंधित हैं, ऐसे सदस्य को अपने पद से हटाने का कोई तरीका नहीं होगा जो अपने नामांकन के बाद और अपने चुनाव से पहले

निरर्हतो के अधीन हो गया हो क्योंकि, इस तरह की निरर्हतो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 सहपठित संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव याचिका द्वारा चुनाव आयोग में चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। यदि यह एक विसंगति है, तो यह बाद के अधिनियम में एक कमी के कारण उत्पन हुई है जो आसानी से ऐसी आकस्मिकता प्रदान कर सकती थी और इसे प्रतिवादी के संवैधानिक प्रावधानों के रचनात्मक निर्माण के खिलाफ एक तर्क के रूप में नहीं दबाया जा सकता है। दूसरी ओर, अगर अटॉर्नी-जनरल का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल द्वारा एक निर्देश से सबंधित वाले और ऊपर उल्लिखित संसदीय क़ानून की धारा 100 के तहत एक चुनाव याचिका की चुनाव न्यायाधिकरण के द्वारा जांच करने जैसे परस्पर विरोधीभासी निर्णय लिए जा सकते हैं।

बताए गए कारणों से हम नीचे दिए गए विद्वान न्यायाधीश से सहमत हैं कि अनुच्छेद 190(3) और 192(1) केवल उन निरर्हतो पर लागू होते हैं जिनके अनुसार एक सदस्य निर्वाचित होने के बाद उसके अधीन हो जाता है, और यह कि प्रत्यर्थी की निरर्हता जो चुनाव से बहुत पहले उत्पन हुई थी की जांच न तो राज्यपाल और न ही आयोग के क्षेत्राधिकार में है।

हालाँकि, हमने माना है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपीलकर्ता आयोग कोई प्रतिषेध रिट जारी करने में सक्षम नहीं था। अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान न्यायाधीश द्वारा जारी प्रतिषेध रिट को रद्द किया जाता है। हम खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं देते।

अपील स्वीकार की गयी।

अपीलकर्ता और मध्यस्थ के लिए अभिकर्ता जी.एच. राजाध्यक्ष।

प्रत्यर्थी के लिए अभिकर्ता : एस. सुब्रमण्यम।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री पुरण कुमार शर्मा (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।